स्थायी अतिक्रमण,अवैध निर्माण पर भी...

पेज एक का शेष

किया जा रहा अतिक्रमण नजर नहीं आया। इस रास्ते से नगर निगम के कई आला अधिकारी सुबह शाम गुजरते हैं लेकिन उन्हें भी कुछ नजर नहीं आता, उनकी आंखों पर काली कमाई का चश्मा जो चढ़ा होता है। इसी फ्रंटियर कॉलोनी में कई अवैध भवन निर्माणाधीन अवस्था में ही सील कर दिए गए थे लेकिन नगर निगम के खाऊ कमाऊ अधिकारियों और उनके दलालों के सहयोग से सील तोड़कर उन्हें बनने दिया गया, कागजों में आज भी सील इन भवनों में व्यावसायिक गतिविधियां चल रही हैं। इसी तरह एनआईटी 3 जे 1 के मालिकों पर एसजीएम नगर में अवैध निर्माण का मुकदमा दर्ज होने के बावजूद यह न सिर्फ बनकर तैयार हुआ बल्कि इसमें गेस्ट हाउस और दुकानें भी चल रही हैं।

तोड़फोड़ दस्ता नगर निगम अधिकारियों का कमाऊ पूत है, इसमें वही अधिकारी रखे जाते हैं जो खुद कमाई करें और ऊपर तक पहुंचाएं और नेताओं की जी हुजूरी कर उनकी मंशा से चुन-चुन कर तोड़फोड़ करें। एसडीओ सुमेर सिंह, जेई प्रवीण बैंसला, अमर पाल बेलदार इन कामों में माहिर हैं, इनके आगे मुख्यमंत्री उड़नदस्ते की रिपोर्ट भी फेल हो जाती है। मुख्यमंत्री उड़नदस्ते ने एनआईटी दो और तीन में कई अवैध निर्माण की रिपोर्ट नगर निगम को भेजी लेकिन सुमेर सिंह और उनकी टीम ने कोई कार्रवाई नहीं की, क्योंकि यह अवैध निर्माण और अतिक्रमण उनके ही संरक्षण में कराया गया था।

नेताओं, अधिकारियों, भू माफिया के प्रिय होने के कारण ही ये लोग लंबे समय से तोड़फोड़ विभाग में टिके हुए हैं।

यदि निगमायुक्त मोना ए श्रीनिवास सच में शहर को अतिक्रमण और अवैध निर्माण मुक्त करने की सही नीयत रखती हैं तो सबसे पहले तोड़फोड़ दस्ते को ही बदल कर ढंग के लोग लगाएं। शहर में अवैध-निर्माण और अतिक्रमण की नगर निगम की ही नहीं खुफिया विभाग और सीएम फ्लाइंग की रिपोर्ट भी हैं। इन रिपोर्टों के आधार पर अवैध निर्माणों पर जेसीबी चलवाएं, जो उनके लिए आसान नहीं होगा। अब यह उन पर निर्भर है कि वह ईमानदारी से काम करेंगी या फिर भ्रष्ट मातहतों की कठपुतली बनकर लूट कमाई के नेटवर्क में शामिल होंगी।

अधिकारियों के संरक्षण एवं हिस्सापत्ती में ग्रेटर फरीदाबाद में .....

पेज एक का शेष

कृषि भूमि पर व्यावसायिक इस्तेमाल के सवाल पर गोल मोल उत्तर देते हैं। एक बिल्डर ने समझाया कि मुख्यमंत्री खट्टर खुद ही नई कालोनियों को अप्रूव करने की घोषणा कर चुके हैं इसलिए चिंता की बात नहीं है। रजिस्ट्री भी हो जाएगी और निर्माण भी। बिना सीएलयू और सब डिवीजन प्रशासन द्वारा कार्रवाई करने के सवाल पर कहते हैं कि सब कुछ सेट है कोई कार्रवाई नहीं होगी। सैकड़ों लोग प्लॉट खरीद रहे हैं, छह महीने बाद इस रेट पर जमीन नहीं मिलेगी, तुरंत खरीद लीजिए। कुछ बिल्डर तो ये ऑफर करते मिले कि आज इस रेट पर जमीन खरीद लीजिए एक साल बाद तीस से चालीस प्रतिशत अधिक रेट पर वह खुद जमीन खरीद लेंगे।

स्थानीय लोगों के अनुसार नहर पार इलाके में जमीन खरीद फरोख्त का धंधा केंद्रीय मंत्री किशनपाल गूजर के सजातीय कर रहे हैं, अधिकतर को मंत्री का संरक्षण प्राप्त है, कई बड़े प्रॉपर्टी डीलरों के साथ मंत्री खुद बेनामी पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं। यही कारण है कि इतने बड़े पैमाने पर नियम कानून ताक पर रख कर हो रहे अवैध निर्माण पर किसी की नजर नहीं जा रही।

फर्जी डिग्री के बल पर बेलदार से एसडीओ पद पर पहुंचा सुरेंद्र हुडा और नगर निगम की ज्वाइंट कमिश्नर शिखा आंटिल अन्य इलाकों में तो तोड़फोड़ की कार्रवाई करते हैं लेकिन नहरपार ग्रेटर फरीदाबाद में नहीं, क्योंकि यहां से उन्हें मोटी रकम पहुंचाई जाती है जो ऊपर तक बंटती है।

यही हाल डीटीपी एन्फोर्समेंट और हूडा के है। डीटीपी को भूपानी गांव में काफी अंदर हो रहे अवैध निर्माण तो दिखजाते हैं लेकिन ठीक मास्टर रोड के दोनों ओर चल रहा निर्माण नजर नहीं आता, यानी कार्रवाई नहीं होती। हूडा अधिकारी भी अपनी जमीन पर हो रहे अतिक्रमण और अवैध कब्जे को लेकर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। कार्रवाई के नाम पर नोटिस भेजी जाती है और सुविधा शुल्क मिलने के बाद सब ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है।

सरकारी जमीन पर कब्जा और अवैध निर्माण कराने के एवज में काली कमाई करने वाले नगर निगम, हूडा और डीटीपी द्वारा कार्रवाई नहीं किया जाना तो समझ में आता है लेकिन सीएम फ्लाइंग और खुफिया विभाग भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। भरोसेमंद सूत्रों के अनुसार सीएम फ्लाइंग ने एक दो बार यहां रेड की और अवैध निर्माण पकड़ा लेकिन कार्रवाई तो संबंधित विभागों को ही करनी होती है, जो की नहीं जाती। खुफिया विभाग ने शुरू में कई अवैध निर्माण की रिपोर्ट आला अधिकारियों तक भेजीं लेकिन वह उनकी मेज पर ही पडी रह गईं। कार्रवाई नहीं होने के कारण अब खुफिया विभाग भी औपचारिकता ही निभाता है।

सफाई का ढिंढोरा नहीं, कुछ काम करो खट्टर जी

फ़रीदाबाद (मज़दूर मोर्चा) मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने एक अक्तूबर को सेक्टर नौ में समारोहपूर्वक झाड़ू थाम के जनता को स्वच्छता की नसीहत दी। काम तो कोई करना नहीं है सिर्फ फोटो खिंचवा कर ढिंढोरा पीटना, लेकिन जनता अब मोदी-खट्टर के पाखंड को समझ गई है।

खट्टर ने दस साल पहले इसी शहर की कृष्णा कॉलोनी मलिन बस्ती में झाड़ू चलाकर स्वच्छ भारत अभियान की शुरूआत की थी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से वैचारिक बैर रखने वाले राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के कार्यकर्ता मोदी-खट्टर ने उनकी जयंती की अहमियत कम करने के लिए दो अक्तूबर को स्वच्छ भारत अभियान का इवेंट आयोजित करना तो शुरू किया लेकिन आज तक यह ढोल पीटने से ज्यादा कुछ साबित नहीं हो सका।

मोदी-खट्टर हर साल दो अक्तूबर को स्वच्छता अभियान का ढिंढोरा पीटने के लिए नई जगह का चयन करते हैं लेकिन कभी ये देखने की जहमत नहीं करते कि उन्होंने पिछले साल जिस जगह पर झाड़ू चलाई थी वहां क्या हाल है? दस साल पहले खट्टर ने सेक्टर 20 बी स्थित कृष्णा कॉलोनी में जिस जगह झाड़ू चला कर अभियान शुरू किया था वहां आज भी गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, सफाई तो दूर वहां इंटरलॉकिंग सड़क तक नहीं बनाई गई है। होना तो यह चाहिए था कि खट्टर इस बार भी वहीं झाड़ू लेकर पहुंचते जहां उन्होंने दस वर्ष पूर्व यह पाखंड शुरू किया था और देखते कि वहां के क्या हाल हैं। स्थानीय निवासी राजकुमार कहते हैं कि यहां सफाई कर्मी आते ही नहीं, बरसात में कचरा, गोबर और बारिश के पानी के कारण सड़क चलने लायक नहीं रह जाती, बदबू के तो हम लोग आदी हो चुके हैं।

सीएम ने जब यहां स्वच्छता अभियान शुरू किया था तो लगा था कि अब सफाई होगी, इसके उलट यहां और कूड़ा फेका जाने लगा था। डीएमआरसी द्वारा जमीन का बड़ा हिस्सा लिए जाने के कारण अब यहां इस इमारत के चारों ओर कूड़ा-कचरा डाला जाता है।

खट्टर ने सत्ता संभालने के साथ ही शहर की सफाई का जिम्मा चाइनीज कंपनी ईकोग्रीन को दिया था। सरकार का दावा था कि कंपनी कूड़े से बिजली बनाएगी। जो सुविधा अभी तक नगर निगम के जरिए जनता को मुफ्त उपलब्ध थी खट्टर सरकार ने ईकोग्रीन के नाम पर उसके लिए शुल्क बांध दिया। बावजूद इसके शहर स्वच्छ होने के बजाय गंदा होता चला गया। यही कारण है कि स्वच्छता रैंकिंग में फरीदाबाद टॉप सौ शहरों में कभी शामिल नहीं हो सका, हालांकि मुख्यमंत्री हर साल दो साल में यहां झाड़ू लगाते रहे।

वर्तमान में शहर में हर जगह कूड़े के ढेर दिख जाएंगे। न तो सूखे कचरे से बिजली बन सकी और न बायो वेस्ट से खाद। अगर खट्टर की नीयत स्वच्छता अभियान के प्रति साफ है और सफाई कराने की इच्छा है तो झाड़ू लेकर फोटो खिंचवाने के बजाय ईकोग्रीन पर शिकंजा कसें, अगर सही काम नहीं कर रही है तो उसका अनुबंध समाप्त कर दूसरी भारतीय कंपनियों को मौका दें, लेकिन वह ऐसा कर पाएंगे, लगता नहीं है। ऐसा करने की जरूरत भी क्या है जब नाटकबाजी से ही काम चल जाए तो।

अपराधियों का संरक्षक मुंडकटी का थानेदार धर्मेंद्र

फरीदाबाद (मज़दूर मोर्चा) वैसे तो पुलिस कानून व्यवस्था कायम रखने, अपराध रोकने व अपराधियों से आम लोगों को बचाने के लिए होती है लेकिन यदि खुद पुलिस ही अपराधियों से सांठगांठ करके आमजन का जीना हराम कर दे तो लोग कहां जाएं।

मामला वर्ष 2019 का मुंडकटी थाने का है जो अभी मजदूर मोर्चा की जानकारी में आया है। बात अगस्त 2019 की है। गांव औरंगाबाद तह होडल के रहने वाले भूपेंद्र पुत्र जवाहर लाल ने इस थाने में शिकायत दी थी कि अजीत पुत्र ओमप्रकाश व सौरंभी पुत्र अजीत ने उनके घर आकर उनके ताऊ रतिराम के साथ मारपीट की है तथा उसका हाथ तोड़ दिया है। उन्होंने इस मारपीट की एमएलआर भी कटवाई थी लेकिन कई दिन तक चक्कर काटने पर भी पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नही की। इस पर उन्होंने डीजीपी हरियाणा को शिकायत भेजी। डीजीपी आफिस के हस्तक्षेप पर मजबूरी में पुलिस को रिपोर्ट दर्ज करनी पड़ी। मामले की जांच धर्मेंद्र एएसआई के पास थी उसने आरोपितों को बचाने के लिए उसने पीड़ित पक्ष पर सामाजिक दबाव बनवा कर उनसे अपनी देखरेख में गांव के दस आदमियों की मौजूदगी में राजीनामा करवाने का नाटक करते हुए शिकायतकर्ता के कम पढ़े लिखे होने का फायदा उठाकर एक शपथपत्र ले लिया। जिसमे उसने शातिरपन से लिखा दिया कि हमारा कोई झगड़ा नही हुआ बल्कि रात के अंधेरे गिरने से मेरे तो को चोट लग गई थी। एएसआई धर्मेंद्र ने आरोपितों पर फोकट में तो ये कृपा की नही होगी।

इसके बाद पीड़ित पक्ष द्वारा डीजीपी से शिकायत करने का सबक सिखाने के इरादे से खुद धर्मेंद्र एएसआई ने धारा 182 का मुकदमा दर्ज दायर कर दिया जिसके कारण पीड़ित पक्ष आज तक अदालत के चक्कर काट रहा है। गौरतलब है कि भूपेंद्र एक खेतिहर मजदूर है जो खेती किसानी व मजदूरी करके अपने परिवार का गुजर बसर कर रहा है जो आजकल एक भ्रष्ट पुलिस थानेदार के कारण अपनी मजदूरी छोड़कर अदालत के चक्कर काटने को मजबूर है।

वही धर्मेंद्र पदोन्नत होकर वर्तमान में इसी थाने में इंचार्ज नियुक्त हुआ है अब इसे संयोग कहें या एक सोची समझी चाल, उन्ही हमलावरों के परिवार के ही अन्य गुंडों जिनमें गांव के अन्य गुंडे भी थे, से 21 सितंबर की रात को भूपेंद्र पुत्र जवाहर लाल के घर जाकर मारपीट होती है तथा उनके पैसे भी लूट लिए जाते हैं। इसकी शिकायत उसी रात भूपेंद्र के ताऊ के लड़के हेमराज, जो वहीं मौजूद था, ने मुंडकटी थाने में जाकर दी लेकिन आज तक रिपोर्ट दर्ज करना तो दूर किसी गुंडे को पूछताछ के लिए भी नही बुलाया गया है। इतना तो तब है जब पीड़ित पक्ष एएसपी जसलीन कौर को भी लिखित शिकायत दे चुका है। यदि पुलिस इन हमलावर गुंडों को गिरफ्तार करके अपने ढंग से पूछताछ करे तो बहुत सारी वारदात उजागर हो सकती हैं जिन्हे धर्मेंद्र जैसों ने दर्ज ही किया होगा। सवाल यह है कि थाने में बैठे अधिकारियों द्वारा किए जा रहे काले पीले कारनामों की निगरानी करने वाले उच्चाधिकारी क्या करते रहते हैं। क्या उनका दायित्व नहीं है कि अपने मातहत तमाम अधिकारियों की कड़ी निगरानी करें।